CHAPTER-VI

AIACE IN MEDIA

दैनिक भास्कर कोरबा 09-04-2024

खाते एक्टिव करने कोल पेंशनर को फोन कर रहे ठग

सीएमपीएफओ ने सूचना जारी कर किया सतर्क, कहा- रिवाइज्ड पीपीओ में संपर्क कर उठाएं लाभ

भास्कर न्यूज | कोरबा

अंजान मोबाइल नंबरों से खाते एक्टिव करने या फिर सीएमपीएफओ अधिकारी बताकर रिवाइज्ड पीपीओ आवेदन पत्र जमा करने के नाम पर बैंक से जुड़े डिटेल व गोपनीय नंबरों की जानकारी मांगे जाने पर ठगबाजों के झांसे में आने से कोल पेंशनर बचे। इस तरह के कॉल आने पर गोपनीय नंबरों की जानकारी नहीं देने के साथ इनकी ओर से साझा की गई लिंक को क्लिक ना करें। कोल पेंशनरों को सीएमपीएफओ ने सूचना जारी कर सतर्क किया है। रिवाइज्ड पीपीओ व अन्य सेवाएं सीएमपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर लाभ उठाने कहा है।

अंजान नंबरों से इस तरह के कॉल को पेंशनभोगियों की सहायता करने का नाटक करके बड़ी राशि निकाल लेने की दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आने की जानकारी दी है। दरअसल सीएमपीएफओ ने लाभार्थी कोयला पेंशनभोगियों के जीवनसाथी को पेपरलेस और बिना किसी परेशानी के पेंशन का लाभ देने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को रिवाइज्ड करने विशेष अभियान चला रही है। अब क्लेम का भी सी-केयर्स ऑनलाइन तरीके से निपटान कर रही है। कोल पेंशनरों के पीपीओ रिवाइज्ड करने जरूरी दस्तावेज जमा करने कहा है। इस अवसर का ठगबाज गिरोह के सदस्य ठगी करने कोल पेंशनरों को कॉल कर झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमपीएफओ ने जारी सूचना में ठगी की दो घटनाएं भी होना बताया है। कोल पेंशनरों को सतर्क किया है कि रिवाइज्ड पीपीओ या खाता एक्टिव करने के बहाने अंजान नंबरों से कॉल आने पर झांसे में नहीं आएं। रिवाइज्ड पीपीओ व अन्य सेवाओं के लिए कोल पेंशनरों को सीधे सीएमपीएफओ या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करने की सलाह दी है।

पारदर्शी तरीके से निपटाए जाएंगे प्रकरण

सीएमपीएफओ ने कार्यालय में करने वाले दावे पारदर्शी तरीके से निपटाए जाएंगे। जारी सूचना में बताया है कि सीएमपीएफओ पूरी पारदर्शिता की ओर बढ़ रहा है। सेवा में और सेवा से बाहर निकलने पर भी उनके लिए खड़ा है। मगर ऑनलाइन सेवाओं के लागू किए जाने के बीच ठगबाज गिरोह ऑनलाइन धोखाधड़ी करने सक्रिय हो गई है। इस कारण सीएमपीएमओ को कोल पेंशनरों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करनी पड़ी है।

संशोधित पीपीओ के आवंटन में देरी का नतीजा

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (एआईएसीई) के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने बताया कि फर्जी तरीके से कोल पेंशनरों के खाते से लाखों रुपए निकाले जाने की वजह संशोधित पीपीओ क आवंटन में देरी का नतीजा है। अधिकांश कोल पेंशनरों के कम शिक्षित या डिजिटल रूप से अशिक्षित पेंशनभोगियों के लिए नोटिस जारी कर सीएमपीएफओ धोखेबाज के जाल में नहीं फंसने की चेतावनी देकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

दैनिक भास्कर कोरबा 06-04-2024

लेटलतीफी • जीवनसाथी को लाभार्थी की मृत्यु पर पेपरलेस पेंशन भुगतान की मिलेगी सुविधा

कोल पेंशनरों से डेटा जुटाने में देरी के कारण पीपीओ नहीं हो सकी रिवाइज्ड

भास्कर न्यूज | कोरबा

कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के कोल पेंशनरों से डेटा जुटाने में देरी से सभी कोयला पेंशनभोगियों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) रिवाइज्ड नहीं हो पाया है। पीपीओ रिवाइज्ड होने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया होने से जीवनसाथी को लाभार्थी की मृत्यु पर पेपरलेस पेंशन भुगतान की सुविधा मिलेगी। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के फेर में कोयला पेंशनरों के जीवनसाथी को परेशान नहीं होना पड़ेगा और बिना देरी के पेंशन का भुगतान भी हो सकेगा।

कोयला कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। कोल पेंशनरों की मृत्यु पर जीवनसाथी को उसके जीवित रहने तक नियमानुसार पेंशन देने का प्रावधान है। जीवनसाथी को लाभार्थी की मृत्यु पर पेंशन पाने दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे दुख की घड़ी में परेशानी झेलनी पड़ती है। रिटायर्ड कोयला कर्मियों को पेंशन भुगतान करने वाली कोल माइंस पेंशन फंड आर्गेनाइजर (सीएमपीएफओ) के पीपीओ रिवाइज्ड कर ऑनलाइन कर प्रकिया पेपरलेस करने की है। ताकि बिना किसी कागजी कार्रवाई के जीवनसाथी को लाभार्थी की मृत्यु पर पेंशन भुगतान हो सके।

मगर कोल इंडिया की अनेक कोयला कंपनियों ने अब तक कोल पेंशनरों का डाटा नहीं जुटा पाई है। हालांकि इस प्रक्रिया में विलंब होने पर सीआईएल ने अपने सहायक कोयला कंपनियों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर एरिया दफ्तरों में हेल्प डेस्क भी स्थापित की है, मगर रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से भी पीपीओ रिवाइज्ड किए जाने की प्रक्रिया में देरी हुई है।

अब 30 जून के पहले दस्तावेज जमा कराने अपील

कोल इंडिया ने एसईसीएल समेत अन्य सहायक कोयला कंपनियों से रिटायर्ड कोल पेंशनरों को अब 30 जून के पहले अनिवार्य रूप से दस्तावेज अपने संबंधित एरिया कार्यालय में जमा कराने अपील की है। तय प्रारूप में भरकर जरूरी दस्तावेजों समेत कंपनी के पेंशन विभाग में जमा कराना होगा। इससे आश्रित के भविष्य को सुरक्षित होने के साथ निरंतर पेंशन भुगतान हो सकेगा। इस संबंध में कोयला कंपनियों के दफ्तरों में पेंशनरों को जानकारी लेने कहा है।

डाटा जुटाने एआईएसीई के प्रस्ताव अमल में नहीं लाया

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव (एआईएसीई) ने सुझाव दिया था कि कोल पेंशनरों की डाटा पेंशन वितरण बैंको से जुटाई जा सकती है। मगर इसे अमल में नहीं लाया गया है। अनेक कोयला कंपनियां सभी पेंशनभोगियों से अब तक डाटा नहीं जुटा पाया है। जबकि लगभग 7 महीने का लंबा समय गुजर गया है।

नोडल बैंकों को शामिल करने का दिया था सुझाव: महासचिव

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने बताया कि लाभार्थी कोल पेंशनभोगियों की मौत होने पर आसानी से जीवनसाथी की विधवा पेंशन शुरू करने जरूरी डाटा आसानी से जुटाने नोडल बैंकों को शामिल करने सुझाव दिया था, क्योंकि यह डाटा पेंशन वितरण बैंकों से जुटाई जा सकती है। इसको लेकर दोबारा कोल इंडिया के चेयरमैन, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष, सीएमपीएफओ के आयुक्त को पत्र लिखा है।

वाराणसी से प्रकाशित RNI No. UPHIN/2016/68165
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
पूर्वांचल राज्य
4 6
वर्ष : 09 अंक : 64 वाराणसी, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 पृष्ठ : 8 मूल्य : 5.00 रुपए

कोल पेंशनर की सुविधा हेतु दीया मांग पत्र
प्रधान महासचिव पी,के सिंह राठौड़

पूर्वांचल राज्य

वाराणसी। संशोधित पीपीओ जारी करने के लिए आवश्यक डेटा संग्रह के लिए पेंशन वितरण बैंकों को शामिल करने के लिए पत्र संख्या एआईएसीई सेंट्रल 2023/66 दिनांक 25/8/2023 के माध्यम से एआईएसीई के पहले के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का सीएमपीएफओ द्वारा कोयला कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवनसाथी के नाम और उनकी तस्वीरों सहित सभी आवश्यक डेटा एकत्र करने के बाद पीपीओ जारी किया जाता है। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बैंक बिना किसी समस्या के पेंशन का वितरण करता है । अधिकांश पेंशनभोगियों ने अपने पेंशन खाते को 'पूर्व या उत्तरजीवी के रूप में परिवर्तित कर लिया है।

विधवा पेंशन को सुचारू रूप से शुरू करने की सुविधा के लिए, संशोधित पीपीओ जारी करने हेतु, जीवनसाथी का आधार कार्ड, पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो) और अन्य डेटा एकत्र करने की कवायद शुरू की गई है, जिनमें से अधिकांश डाटा कंपनी, सीएमपीएफओ और पेंशन वितरण बैंकों के पास पहले से ही उपलब्ध हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए और सराहना की जानी चाहिए कि एआईएसीई एआईसीपीए लाभार्थियों की मृत्यु के मामले में जीवनसाथी को परेशानी मुक्त पेंशन शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

जीवनसाथी को पेंशन शुरू करने के लिए, केवल लाभार्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है क्योंकि आधार कार्ड, जीवनसाथी का पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो), पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के पास उपलब्ध हैं।

धोखेबाजों से सावधान रहने को रिटायर्ड कर्मियों को करें जागरूक

- कोल इंडिया जीएमपी ने कोल कंपनियों के सभी जीएमपी को लिखा पत्र, किया आगाह
- रिटायर्ड कोलकर्मी के साथ ठगी की घटना के बाद गंभीर हुआ प्रबंधन

वरीय संवाददाता, धनबाद

पीपीओ फॉर्म जमा करने में अंजान से न लें मदद

निर्देश में कहा गया कि सभी कोल कंपनियां अपने कंपनी के सभी रिटायर्ड कर्मी को विभिन्न संचार माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, नोटिस, बल्क मैसेज आदि के माध्यम से ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए जागरूक करें और संशोधित पीपीओ फॉर्म जमा करने के संबंध में किसी भी जानकारी/मदद के लिए सीधे सीएमपीएफओ या संबंधित अधिकृत नोडल अधिकारियों से संपर्क करें.

कोल इंडिया प्रबंधन ने बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल समेत सभी सहायक कंपनियां धोखेबाजों से सावधान रहने के लिए रिटायर्ड कोलकर्मियों को जागरूक करने की अपील की है. इस बाबत शुक्रवार को कोल इंडिया के जीएमपी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी की गयी है.

इसमें कोल इंडिया जीएमपी ने कहा : कोल इंडिया व उसकी अन्य सभी सहायक कंपनियों द्वारा कंपनी के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के संबंध में संशोधित पीपीओ फॉर्म जमा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. परंतु अभी हाल ही में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कोल इंडिया जीएमपी ने कहा कि कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को एक धोखेबाज ने दस लाख रुपये की ठगी की थी, जो सीएमपीएफओ अधिकारी होने का दिखावा कर रहा था और संबंधित रिटायर्ड कोलकर्मी को संशोधित पीपीओ फॉर्म जमा करने में सहायता करने का प्रयास कर रहा था.

स्कैन करें

पुराने रिटायर कोल कर्मियों की न्यूनतम पेंशन ₹1000 हुई

धनबाद, विशेष संवाददाता। रिटायर कोयला कर्मियों की न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए करने संबंधी सीएमपीएफओ (कोयला खान भविष्य निधि संगठन) ट्रस्टी बोर्ड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इससे 1.2 लाख रिटायर कोयला कर्मी लाभान्वित होंगे। कोयला मंत्री प्र''ाद जोशी ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है।

कोयला मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है कि कोयला क्षेत्र में पेंशनभोगियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर रुपए 1000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दे दी है। कोयला खदान पेंशन योजना 1998 के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह

1.2 लाख रिटायर कोयला कर्मी होंगे लाभान्वित

- बोर्ड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने दी हरी झंडी
- कोयला मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

का लाभ लगभग 1.2 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वैसे पेंशनर जिनको एक हजार से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें अब कम से कम एक हजार पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह मील का पत्थर है। सीएमपीएफओ बोर्ड ने सितंबर-2023 में ही दिल्ली में आयोजित बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन एक हजार करने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। बोर्ड से स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था। लगभग छह माह तक वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव रहा। अब मंजूरी दी गई है।

मालूम हो कि कोल सेक्टर में काफी पहले रिटायर हुए कोयला कर्मियों को अभी दो सौ-चार सौ पेंशन मिलती है। इनकी संख्या लगभग एक लाख है। पेंशनर एसोसिएशन न्यूनतम पेंशन पांच हजार करने की मांग करती रही है। वैसे सीएमपीएफओ ने ईपीएफओ की तर्ज पर न्यूनतम पेंशन एक हजार करने का निर्णय लिया। न्यूनतम पेंशन एक हजार करने संबंधी आधिकारिक पत्र अबतक सीएमपीएफओ नहीं पहुंचा है।

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करेगी सरकार

एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दी जानकारी

बैतूल एक्सप्रेस, सिटी

ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षों से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़, बीके श्रीवास्तव एवं समस्त वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी रुपिंदर बरार, संजोजक पीके सिंह राठौर, दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उपाध्यक्ष, बीके श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि कोल पेंशनरों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मार्च के पहले सप्ताह में बिलासपुर में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें पेंशनर संघो को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में हमारी मांगों को यदि नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।

ऑल इंडिया कोयला पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईसीपीए) 2018 ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (एआईएसीइ)

वाराणसी। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (एआईसीपीए) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जीक्यूटिव्स (एआईएसीई) ने सीएमपीएस 1998 के तहत पेंशन के संशोधन के लिए 12 फरवरी, 2024 को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया था। मंत्रालय को दिए गए धरने के नोटिस के जवाब में 31/1/24 को कोयला मंत्रालय में सीएमपीएफ आयुक्त द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। एआईएसीई के प्रतिनिधियों यथा श्री पी.के. सिंह राठौड़, प्रधान महासचिव, एआईएसीई, श्री अब्दुल कलाम, अध्यक्ष, एआईएसीई दिल्ली शाखा और डॉ. बी. के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एआईएसीई ने उक्त बैठक में भाग लिया था, जिसमें श्रीमती रूपिंदर बरार, अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय के साथ श्रीमती संतोष अग्रवाल, डीडीजी, कोयला मंत्रालय और श्री वी.के. मिश्रा, आयुक्त, सीएमपीएफओ ने सरकार का पक्ष रखा था। सीएमपीएस-1998 पेंशन वृद्धि पर सार्थक चर्चा हुई। एआईएसीई टीम सरकारी अधिकारियों के सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित हुई। श्रीमती बरार ने मुद्दे के समाधान हेतु सकारात्मक चर्चा के आलोक में 12 फरवरी के धरना को समाप्त करने का अनुरोध किया।

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का मिला आश्वासन

बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। आल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षो से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने आल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़, बीके श्रीवास्तव एवं समस्त वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी रुपिंदर बरार, संजोजक पीके सिंह राठौर, दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उपाध्यक्ष, बीके श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि कोल पेंशनरों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मार्च के पहले सप्ताह में बिलासपुर में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें पेंशनर संघो को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जामकारी दी गई कि मांगों को यदि नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करेगी सरकार

बैतूल टॉक्स, बैतूल

ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षो से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़ मौजूद रहे।

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करेगी सरकार

राजवीर टाईम्स, बैतूल

Raveer Times

ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षो से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़, बीके श्रीवास्तव एवं समस्त वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी रुपिंदर बरार, संजोजक पीके सिंह राठौर, दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उपाध्यक्ष, बीके श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि कोल पेंशनरों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मार्च के पहले सप्ताह में बिलासपुर में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें पेंशनर संघो को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में हमारी मांगों को यदि नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।

विचार - प्रकाश

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करेगी सरकार, एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने दी जानकारी

बैतूल। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षो से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़, बीके श्रीवास्तव एवं समस्त वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी रुपिंदर बरार, संजोजक पीके सिंह राठौर, दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उपाध्यक्ष, बीके श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि कोल पेंशनरों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मार्च के पहले सप्ताह में बिलासपुर में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें पेंशनर संघो को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में हमारी मांगों को यदि नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।

कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करेगी सरकार

बैतूल,ताप्ती समन्वय। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एआईसीपीए की आपातकालीन बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में बैतूल जिले से कोल माइंस सेवानिवृत कर्मचारी संघ, एचएमएस संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बैतूल जिले के एचएमएस पदाधिकारियों को अवगत कराया कि सरकार ने कोल पेंशनरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है इसलिए 12 फरवरी को आयोजित धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

एचएमएस संगठन के जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया कि विगत तीन-चार वर्षो से की गई मेहनत का नतीजा है कि सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है। महासचिव डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पीके सिंह राठौड़, बीके श्रीवास्तव एवं समस्त वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में कोल मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी रुपिंदर बरार, संजोजक पीके सिंह राठौर, दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम उपाध्यक्ष, बीके श्रीवास्तव शामिल हुए। बैठक में सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि कोल पेंशनरों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मार्च के पहले सप्ताह में बिलासपुर में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। जिसमें पेंशनर संघो को भी आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में हमारी मांगों को यदि नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन के लिए फिर निर्णय लिया जाएगा।

मांगें नहीं मानीं तो कोलकाता में 22 को धरना देंगे कोल पेंशनर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बैतूल. कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की मासिक बैठक सोमवार 15 जनवरी को शहीद भवन में हुई। बैठक में सभी कोल पेंशनरों ने निर्णय लिया कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी को कोलकाता तथा 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। अध्यक्ष डीके साहू ने सभी कोल पेंशनरों को यह भी बताया कि आज कोल इंडिया के सीएमडी ने कोल पेंशनरों की पांच सूत्री मांगों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। पीके सिंह राठौड़ को पांच सदस्यों के साथ मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी से भी पेंशनरों को अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया 4 जनवरी को नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य राकेश कुमार से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि जिन कोल पेंशनर को 1 हजार से कम पेंशन मिल रही है उन्हें अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें अध्यक्ष द्वारा पत्र प्रदान किया गया। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, दिनेश शर्मा, पूरनलाल मालवीय, आरडी सोनी, अजाबराव भूमरकर, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, राजेश अवस्थी, मानक प्रसाद वाईकर, एमपी मिश्रा, तुलसीराम, दौलत मालवी, शिवप्रसाद मालवी, रूपलाल पाल आदि उपस्थित थे।

मांगे नहीं मानी तो 22 को कोलकाता में धरना देंगे कोल पेंशनर

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की बैठक में लिया निर्णय

सतपुड़ा सागर, बैतूल

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की मासिक बैठक सोमवार 15 जनवरी को शहीद भवन में संपन्न हुई। बैठक में सभी कोल पेंशनरों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी को

कोलकाता तथा 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। अध्यक्ष डीके साहू ने सभी कोल पेंशनरों को यह भी बताया कि आज कोल इंडिया के सीएमडी ने कोल पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांगों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। पीके सिंह राठौड़ को पांच सदस्यों के साथ मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी से भी पेंशनरों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 जनवरी को नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य राकेश कुमार से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि जिन कोल पेंशनर को 1 हजार से कम पेंशन मिल रही है उन्हें अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें अध्यक्ष द्वारा पत्र प्रदान किया गया। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, दिनेश शर्मा, पूरनलाल मालवीय, आरडी सोनी, अजाबराव भूमरकर, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, राजेश अवस्थी, मानक प्रसाद वाईकर, एमपी मिश्रा, तुलसीराम, दौलत मालवी, शिवप्रसाद मालवी, रूपलाल पाल आदि उपस्थित थे।

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स (एआईसीपीए) अखिल भारतीय कोयला कार्यकारी संघ (एआईएसीई) कोलकाता, सिंगरेनी और जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना

पूर्वांचल राज्य

वाराणसी। अधिकारियों के वेतन संघर्ष, सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा मुद्दों पर स्थिति का जायजा लेने के लिए जूम प्लेटफॉर्म पर एआईसीपीए और एआईएसीई की एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी।

श्री. एआईएसीई/एआईसीपीए के संयोजक पी.के.सिंह राठौड़ ने सदस्यों का स्वागत किया और श्री से अनुरोध किया। बैठक की अध्यक्षता एआईएसीई के अध्यक्ष आर.बी.माथुर करेंगे। उन्होंने श्री अब्दुल कलाम का भी स्वागत किया। उन्होंने डॉ. बी.के.श्रीवास्तव से पिछले कुछ महीनों के दौरान गतिविधियों का सारांश देने का अनुरोध किया।

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि संयोजक ने 16 अक्टूबर 23 को सीआईएल के अध्यक्ष के साथ-साथ निदेशक (पी एंड आईआर) से

मुलाकात की थी और उन्हें कामकाजी और सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने आने वाले मुद्दों से अवगत कराया था। मुख्य मुद्दे एनसीडब्ल्यूए-क से उत्पन्न वेतन संघर्ष, अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए पेंशन और सीपीआरएमएस में संशोधन हैं। अध्यक्ष और निदेशक (पी एंड आईआर) दोनों ने मुद्दों को सुना और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और एसोसिएशन से 30 अक्टूबर 23 को होने वाले प्रदर्शन के नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया। अध्यक्ष एसोसिएशन के इस सुझाव से प्रभावित हुए कि इसके बजाय 10 रुपये प्रति मीट्रिक टन का उपकर (20 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव), जो वर्तमान में स्वैच्छिक है, यह पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कोयले की बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में होना चाहिए।

श्री राठौड़ ने बताया कि लगभग दो महीने बीत चुके हैं लेकिन सीआईएल प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है और उन्होंने भाग लेने वाले सदस्यों से आम राय मांगी कि अब क्या करना है।

भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के आधार पर निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

1. हमारी जायज मांगों को सीआईएल चेयरमैन को सौंपे हुए दो महीने से ज्यादा हो गया है.
2. सीआईएल अध्यक्ष को सीएमपीएस-98 के संशोधन के विषय पर बीसीसीएल, एसईसीएल के पूर्व सीएमडी, श्री आर.बी.नाथूर द्वारा एक अभ्यावेदन भी सौंपा गया।
3. अंत में, यह निर्णय लिया गया कि वेतन संघर्ष के समाधान, अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के लिए पेंशन और सीपीआरएमएस में संशोधन आदि की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एआईसीपीए और एआईएसीई 22 जनवरी, 2024 को सीआईएल, कोलकाता और एससीसीएल कोठागुडेम के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे।

जबकि वह चाहती थी कि उसके घर बेटी हो जाए।

प्रदर्शनः मांगें नहीं मानी तो 22 को कोलकाता में धरना देंगे कोल पेंशनर

बैतूल » रिपोर्टर

22 जनवरी होगा धरना प्रदर्शन

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की मासिक बैठक सोमवार 15 जनवरी को शहीद भवन में संपन्न हुई। बैठक में सभी कोल पेंशनरों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी को कोलकाता तथा 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। अध्यक्ष डीके साहू ने सभी कोल पेंशनरों को यह भी बताया कि आज कोल इंडिया के सीएमडी ने कोल पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांगों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। पीके सिंह राठौड़ को पांच सदस्यों के साथ मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी से भी पेंशनरों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 जनवरी को नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य राकेश कुमार से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि जिन कोल पेंशनर को 1 हजार से कम पेंशन मिल रही है उन्हें अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें अध्यक्ष द्वारा पत्र प्रदान किया गया। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, दिनेश शर्मा, पूरनलाल मालवीय, आरडी सोनी, अजाबराव भूमरकर, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, राजेश अवस्थी, मानक प्रसाद वाईकर, एमपी मिश्रा, तुलसीराम, दौलत मालवी, शिवप्रसाद मालवी, रूपलाल पाल आदि उपस्थित थे।

सर्वजन पेंशन से भी कम पेंशन मिलती है कोयलाकर्मियों को

मनोज सिंह, रांची

- 1999 में रिटायर सीएमडी–निदेशक को मिलती है दो से तीन हजार पेंशन, 1998 से नहीं हुई है समीक्षा

कोल इंडिया की कंपनियों में सीएमडी और निदेशक के पद से वर्ष 1999-2000 के आसपास रिटायर होनेवाले कई अधिकारियों को अभी दो से तीन हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह मिलती है. अधिकारी के आश्रित को 1200 से 1800 रुपये तक पेंशन मिल रही है. वहीं, इस दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 500-600 रुपये भी पेंशन मिल रही है. यह झारखंड सरकार के सर्वजन पेंशन स्कीम से भी कम है.

झारखंड सरकार सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को एक हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह दे रही है. झारखंड सरकार विधवा को भी एक हजार रुपये पेंशन इसी स्कीम के तहत दे रही है. असल में कोल इंडिया के कर्मियों को कोल माइंस पेंशन स्कीम-1999 के तहत पेंशन का भुगतान होता है. यह 1998 से लागू है. 25 साल बाद भी पेंशन को लेकर कोई समीक्षा नहीं की गयी है.

कंपनी का पेंशन बंद कराने की मांग की है कई रिटायर कर्मियों ने : ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कई रिटायर कर्मियों ने कंपनी की पेंशन बंद कराने का आग्रह किया है. उनका कहना है कि कई राज्यों में सरकार से जो पेंशन मिल रही है, वह कंपनी के पेंशन से अधिक है. कई राज्यों में एक हजार से 1500 से अधिक पेंशन मिल रही है.

ऐसे तय होती है पेंशन : कोयलाकर्मियों की पेंशन कार्यरत अंतिम 10 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के औसत के आधार पर तय होती है. 10 माह के मूल वेतन और औसत का 25 फीसदी पेंशन दी जाती है. अगर किसी कर्मी या अधिकारी की मौत सेवानिवृत्ति के बाद हो जाती है, तो उसके परिजन को मूल पेंशन का 60 फीसदी दिया जाता है.

क्या कहते एसोसिएशन के सदस्य : ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के संयोजक पीके सिंह राठौर कहते हैं कि पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर हम लोग वर्षों से संघर्षरत हैं. कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं. हमलोग चाहते हैं कि पेंशन बढ़ायी जाये. पेंशन फंड में कोयला के विक्रय मूल्य का एक तय प्रतिशत डाला जाये. जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा.

पेंशन एक हजार से कम

कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों से रिटायर करीब 3.96 लाख कर्मी पेंशन पा रहे हैं. इसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं. इन पर हर साल करीब 4500 करोड़ रुपये खर्च होता है. कोल इंडिया से 1999 के बाद रिटायर करीब एक लाख कर्मी को प्रति माह एक हजार रुपये से भी कम पेंशन मिलती है. कोल इंडिया के कर्मियों को पहले कम वेतन मिलता था. पांचवें वेतन समझौते (1996) के बाद से पेंशन स्कीम लागू किया गया था. उस वक्त एक कर्मी का न्यूनतम वेतन करीब 2100 रुपये के आसपास था.

पेंशनरों ने सौंपा ज्ञापन, कहा- 31 तक मांगें पूरी करें

कोल माइंस सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।

बैतूल. कोल माइंस सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस ने शुक्र वार प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके पूर्व शहीद भवन में समस्त कोल माइंस पेंशनरों की बैठक की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ अध्यक्ष डीके साहू ने बताया हमारी 6 सूत्री मांगों में कोयला खान पेंशन योजना के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 18 मार्च 2020 को संसद में प्रस्तुत है के सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करें। पेंशन रिवीजन प्रत्येक 3 वर्षों के अनुपात में वर्ष 1998 से 2023 तक 25 वर्षों का पेंशन रिवीजन कर भुगतान करें। पेंशन में संशोधन बेसिक का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत पेंशन दिलाई जाए। पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़कर दिलाया जाए। सभी कोल पेंशनर कर्मचारियों को डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस 3 हजार प्रति माह पेंशन के साथ जोड़ कर दिया जाए। 2017 से 2018 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं उन्हें भी ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मांग पत्र का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी 2024 को सीआईएल के सीएमडी कार्यालय कोलकाता में तथा 12 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर देश की पांचों ट्रेड यूनियन तथा अन्य 22 पेंशन समितियां के साथ में देश के 17 राज्यों से पेंशन भोगी धरना प्रदर्शन करेंगे।

कोयला पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

मांग पूरी नहीं होने पर जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी

बैतूल,तासी समन्वय। हिन्द मजदूर सभा बैतूल से जुड़े कोयला पेंशनर्स ने आज (शुक्रवार को) 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम लेकर ज्ञापन सौंपा।

बता दें कि पेंशनर्स लंबे समय से पेंशन रिवीजन समेत मंहगाई भत्ते, मेडिकल अलाउंस की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स ने बताया कि 2 महीने पहले सी.आई.एल. चेयरमैन को हमारी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। पूर्व सी.एम.डी.सी.आर.बी. माथुर को भी पत्र दिया था। लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। 2016 से कई बार कोयला मंत्री को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। वर्ष 2019, 2021, 25 जुलाई 2022 एवं 5 दिसंबर.2022 को जंतर-मंतर पर धरना भी दिया जा चुका है। लेकिन उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया।

यदि 31 दिसम्बर 2023 तक हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन के संयोजक पी.के. सिंह राठौर के आवाहन पर 22 जनवरी 2024 को सी.आई.एल.सी.एम.डी. के कार्यालय कलकत्ता में प्रदर्शन किया जाएगा तथा 12 फरवरी 2024 को पुनः जंतर-मंतर नई दिल्ली पर धरना दिया जाएगा।

यह कर्मचारियों की मांग

कोयला खान पेंशन योजना के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (18 मार्च 2020 को सांसद में प्रस्तुत) में निहित सुझावों का त्वरित कार्यान्वयन हो।

पेंशन रिवीजन प्रत्येक तीन वर्षों के अनुपात में वर्ष 1998 से वर्ष 2023 तक 25 वर्षों का पेंशन रिवीजन कर भुगतान किया जाए।

पेंशन संशोधन का बेसिक का 25% से बढ़ाकर 50% पेंशन दिलाया जाए।

पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता (DA) जोड़कर दिया जाए।

सभी कोल कर्मचारियों को भी डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस 3000/- (तीन हजार) रूपए प्रतिमाह पेंशन के साथ दिया जाए।

वर्ष 2017 से 2018 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए है. उन्हें भी ग्रैचुइटी का लाभ दिया जाए।

31 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमडी कार्यालय कोलकाता में देंगे धरना

प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

गुरुमंत्र रिपोर्टर बैतूल

कोल माइंस सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस ने शुक्रवार 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके पूर्व शहीद भवन में समस्त कोल माइंस पेंशनरों की बैठक आयोजित की गई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष डीके साहू ने बताया हमारी 6 सूत्रीय मांगों में कोयला खान पेंशन योजना के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 18 मार्च 2020 को संसद में प्रस्तुत है के सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करें। पेंशन रिवीजन प्रत्येक 3 वर्षों के अनुपात में वर्ष 1998 से 2023 तक 25 वर्षों का पेंशन रिवीजन कर भुगतान किया जाए। पेंशन में संशोधन बेसिक का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत पेंशन दिलाई जाए। पेंशन के साथ

महंगाई भत्ता डीए जोड़कर दिलाया जाए। सभी कोल पेंशनर कर्मचारियों को डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस 3 हजार प्रति माह पेंशन के साथ जोड़ कर दिया जाए। 2017 से 2018 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं उन्हें भी ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मांग पत्र का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी 2024 को सीआईएल के सीएमडी कार्यालय कोलकाता में तथा 12 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर देश की पांचो ट्रेड यूनियन तथा अन्य 22 पेंशन समितियां के साथ में देश के 17 राज्यों से पेंशन भोगी आकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बैतूल एचएमएस से लगभग 100 सदस्य भाग लेंगे। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, अजाबराव भूमरकर, दिनेश शर्मा, एनपी मिश्रा, बीआर गावंडे, अशोक सेलकरी, साहेबराव देशमुख, आरडी सोनी, एलएन रायपुरे, पूरनलाल मालवीय, लेखराम, सरजेराव पाटिल, मानक प्रसाद वाईकर, कीर्तिराम उबनारे, सीपी साहू, रायमल वरवड़े, शिवकुमार धामसे, रूपलाल पाल, सुखराम पवार, बाबूलाल मालवी, डीआर चिल्हाटे, बारेलाल भूमरकर, सुखराम यादव, सुखराम पवार, तुलसीराम मासोदकर, कुंदन पवार, पूरनलाल मालवीय उपस्थित थे।

कोल माइंस रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन रिवीजन कर मांगा भुगतान

31 दिसंबर तक मांगू पूरी नहीं हुई तो सीएमडी कार्यालय में देंगे धरना

बैतूल| कोल माइंस सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संघ ने पेंशन रिवीजन कर भुगतान करने सहित अन्य मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। 31 दिसंबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर सीएमडी कार्यालय कोलकत्ता में धरना देने की चेतावनी दी है। संघ के अध्यक्ष डीके साहू ने बताया कोयला खान पेंशन योजना के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 18 मार्च 2020 को संसद में प्रस्तुत है। इसके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करने, वर्ष 1998 से 2023 तक 25 वर्षों का पेंशन रिवीजन कर भुगतान करने, पेंशन में संशोधन बेसिक का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत पेंशन दिलाने, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़कर दिलाने, कोल पेंशनर कर्मचारियों को डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस 3 हजार प्रति माह पेंशन के साथ जोड़ कर देने सहित अन्य मांगे रखी है।

इसके बाद विभिन्न मांगों को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि 31 दिसंबर तक भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मांग पत्र का समाधान नहीं किया तो आगामी समय में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आह्वान पर 22 जनवरी को सीआईएल के सीएमडी कार्यालय कोलकाता में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान महामंत्री डीआर झरबड़े, अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, अजाबराव भूमरकर, दिनेश शर्मा, एनपी मिश्रा, बीआर गावंडे, अशोक सेलकरी, साहेबराव देशमुख, आरडी सोनी, एलएन रायपुरे, पूरनलाल मालवीय सहित अन्य रिटायर्ड कर्मचारी मौजद थे।

sh.com/
nadesh बैतूल, शनिवार 16 दिसंबर 2023 2

31 तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमडी कार्यालय कोलकाता में देंगे धरना

» प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

बैतूल (राष्ट्रीय जनादेश)। कोल माइंस सेवा निवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस ने शुक्रवार 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके पूर्व शहीद भवन में समस्त कोल माइंस पेंशनरों की बैठक आयोजित की गई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष डीके साहू ने बताया हमारी 6 सूत्रीय मांगों में कोयला खान पेंशन योजना के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 18 मार्च 2020 को संसद में प्रस्तुत है के सुझावों पर त्वरित कार्यवाही करें। पेंशन रिवीजन प्रत्येक 3 वर्षों के अनुपात में वर्ष 1998 से 2023 तक 25 वर्षों का पेंशन रिवीजन कर भुगतान किया जाए। पेंशन में संशोधन बेसिक का 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत पेंशन दिलाई जाए। पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीए जोड़कर दिलाया जाए। सभी कोल पेंशनर कर्मचारियों को डोमेस्टिक मेडिकल अलाउंस 3 हजार प्रति माह पेंशन के साथ जोड़ कर दिया जाए। 2017 से 2018 के बीच जो कर्मचारी सेवानिवृत हुए हैं उन्हें भी ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मांग पत्र का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी 2024 को सीआईएल के सीएमडी कार्यालय कोलकाता में तथा 12 फरवरी 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर देश की पांचो ट्रेड यूनियन तथा अन्य 22 पेंशन समितियां के साथ में देश के 17 राज्यों से पेंशन भोगी आकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बैतूल एचएमएस से लगभग 100 सदस्य भाग लेंगे। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, अजाबराव भूमरकर, दिनेश शर्मा, एनपी मिश्रा, बीआर गावंडे, अशोक सेलकरी, साहेबराव देशमुख, आरडी सोनी, एलएन रायपुरे, पूरनलाल मालवीय, लेखराम, सरजेराव पाटिल, मानक प्रसाद वाईकर, कीर्तिराम उबनारे, सीपी साहू, रायमल वरवड़े, शिवकुमार धामसे, रूपलाल पाल, सुखराम पवार, बाबूलाल मालवी, डीआर चिल्हाटे, बारेलाल भूमरकर, सुखराम यादव, सुखराम पवार, तुलसीराम मासोदकर, कुंदन पवार, पूरनलाल मालवीय उपस्थित थे।

मांगे नहीं मानी तो 22 को कोलकाता में धरना देंगे कोल पेंशनर

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की बैठक में लिया निर्णय

सतपुड़ा सागर, बैतूल

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की मासिक बैठक सोमवार 15 जनवरी को शहीद भवन में संपन्न हुई। बैठक में सभी कोल पेंशनरों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी को

कोलकाता तथा 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। अध्यक्ष डीके साहू ने सभी कोल पेंशनरों को यह भी बताया कि आज कोल इंडिया के सीएमडी ने कोल पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांगों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। पीके सिंह राठौड़ को पांच सदस्यों के साथ मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी से भी पेंशनरों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 जनवरी को नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य राकेश कुमार से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि जिन कोल पेंशनर को 1 हजार से कम पेंशन मिल रही है उन्हें अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें अध्यक्ष द्वारा पत्र प्रदान किया गया। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, दिनेश शर्मा, पूरनलाल मालवीय, आरडी सोनी, अजाबराव भूमरकर, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, राजेश अवस्थी, मानक प्रसाद वाईकर, एमपी मिश्रा, तुलसीराम, दौलत मालवी, शिवप्रसाद मालवी, रूपलाल पाल आदि उपस्थित थे।

जबकि वह चाहता था कि उसके घर बेटा ही जाए।

प्रदर्शनः मांगें नहीं मानी तो 22 को कोलकाता में धरना देंगे कोल पेंशनर

बैतूल » रिपोर्टर

22 जनवरी होगा धरना प्रदर्शन

कोलमाइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एचएमएस की मासिक बैठक सोमवार 15 जनवरी को शहीद भवन में संपन्न हुई। बैठक में सभी कोल पेंशनरों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आव्हान पर 22 जनवरी को कोलकाता तथा 12 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जिला बैतूल से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। अध्यक्ष डीके साहू ने सभी कोल पेंशनरों को यह भी बताया कि आज कोल इंडिया के सीएमडी ने कोल पेंशनरों की पांच सूत्रीय मांगों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई है। पीके सिंह राठौड़ को पांच सदस्यों के साथ मीटिंग में बुलाया गया है। मीटिंग में क्या होगा इसकी जानकारी से भी पेंशनरों को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 4 जनवरी को नागपुर में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य राकेश कुमार से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने बताया कि जिन कोल पेंशनर को 1 हजार से कम पेंशन मिल रही है उन्हें अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिला कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से दिनेश शर्मा को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत कर उन्हें अध्यक्ष द्वारा पत्र प्रदान किया गया। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबडे, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, माणिकराव कापसे, दिनेश शर्मा, पूरनलाल मालवीय, आरडी सोनी, अजाबराव भूमरकर, रामदास पंडाग्रे, नागोराव वागद्रे, राजेश अवस्थी, मानक प्रसाद वाईकर, एमपी मिश्रा, तुलसीराम, दौलत मालवी, शिवप्रसाद मालवी, रूपलाल पाल आदि उपस्थित थे।